JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में सिडकुल में स्थापित औद्योगिकरण का योगदान

डॉ0 दीपक खाती
असिस्टेंट प्रोफेसर
वाणिज्य संकाय
पी0 एन0 जी0 राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय रामनगर, नैनीताल

नुरून्निशा
शोध छात्रा
वाणिज्य संकाय
पी0 एन0 जी0 राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय रामनगर, नैनीताल

सारांश

हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित उत्तराखण्ड प्रकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीप होने के कारण महत्वपूर्ण बाजार में पहुंच के साथ– साथ कच्चे माल की उपलब्धता भी सुगमता से हो जाती है। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए वर्ष 2003 में स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य में तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ है। उद्योगों के अनुकूल नीतियों एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण ने राज्य को आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया है।

की वार्डः– आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, औद्योगिक नीतियां

परिचय

दैदिव्यमान हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखण्ड राज्य दिनांक 9 नवम्बर 2000 को उत्तरप्रदेश से पृथ्कीकरण के फलस्वरूप देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उत्तराखण्ड राज्य को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए दो मण्डलो, कुमाँऊ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल में विभाजित किया गया है। राज्य के 13 जिलों में से कुमाँऊ मण्डल में 6 जिलें (नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर, पिथोरागढ़, चम्पावत और बागेश्वर हैं) एवं गढ़वाल मण्डल में 7 जिले (हरिद्वार, देहरादून, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी) हैं। राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय है, जिसके कारण यहाँ उद्योगो को स्थापित करना एक बहुत बड़ी समस्या है।

उत्तराखण्ड के विकास के लिए पर्यटन, स्वरोजगार, कृषि, पॉलीहाउस, फलोरिकल्चर, विद्युत उत्पादन, वानिकी, खनन इत्यादि की सम्भावनाओं को तलाशा गया, परन्तु राज्य में औद्योगीकरण ही वह प्रयास है, जिससे आर्थिक विकास की प्राप्ति, हो सकती है। औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तात्कालिक सरकार द्वारा सन् 2002 में सिडकुल की अवस्थापना का लक्ष्य रखा गया, जिसने स्थापित होने के पश्चात् लक्ष्य प्राप्ति में अपनी विशेष भूमिका निभायी है। उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल), उत्तराखण्ड राज्य सरकार का एक उद्यम है। जिसका मुख्यालय देहरादून एवं सेवा व कार्यक्षेत्र उत्तराखण्ड है। सिडकुल को, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने एवं राज्य में औद्योगिक ढाँचे को विकसित करने के लिए 50 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी और 20 करोड़ की राज्य सरकार के माध्यम से पूंजीगत भुगतान के साथ वर्ष 2002 में, एक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया।

सिडकुल ने औद्योगिक और आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए 7 (सात), विश्व इंटरगार्टेड इंडस्ट्रियल एस्टेट (IIE) विकसित किए गए हैं। जिसमें अस्पताल, मॉल, स्कूल, बैंक और हॉटल तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक और अवशिष्ट संकाय सम्मिलित हैं। उत्तराखण्ड में सिडकुल द्वारा IT पार्क, देहरादून, IIE, हरिद्वार, IIE, पन्तनगर (उधमसिंहनगर), फार्मा सिटी सेलाकुई (उधमसिंहनगर), IIE सितारगंज फेज II (उधमसिंहनगर), IIE कोटद्वार, IIE Escort farm, काशीपुर (उधमसिंहनगर), SIDC हरिद्वार Site II, SIDC बालभरद्रपुर Site II (हरिद्वार), SIDC बाजपुर–1 (उधमसिंहनगर), SIDC बाजपुर–2 (उधमसिंहनगर), SIDC मोहान (अल्मोड़ा), SIDC भीमताल (नैनीताल), SIDC सेलाकुई (देहरादून), गनगारी अवासीय कलोनी बहदराबाद, SIDC तातसु मंजादी, कर्णप्रयाग (चमोली), SIDC खटीमा (उधमसिंहनगर), SIDC काशीपुर (उधमसिंहनगर), टैक्सटाइल पार्क (काशीपुर), टैक्सटाइल पार्क जसपुर, (उधमसिंहनगर), प्लास्टिक पार्क (SPPL) सीतारगंज (उधमसिंहनगर), अरोमापार्क काशीपुर (उधमसिंहनगर), मदन नेगी, इलैक्टॉनिक मैनिफैक्चरिंग कलैस्टर (काशीपुर) नेपाहेमपुर, एल्डीको सिडकुल औद्योगिक पार्क लिमिटेड, फॉर्मासिटी सेलाकुई (देहरादून) इत्यादि है। जिसमें से केवल IT पार्क (देहरादून), IIE हरिद्वार, IIE पन्तनगर (उधमसिंहनगर), फार्मा सिटी सेलाकुई (देहरादून), IIE सितारगंज फेज II¼, IIE कोटद्वार, IIE Escort farm, काशीपुर, SIDC हरिद्वार Site II, SIDC बालभरद्रपुर Site II (हरिद्वार), SIDC बाजपुर–1, SIDC बाजपुर–2, SIDC मोहान, SIDC भीमताल, SIDC सेलाकुई (देहरादून), क्षेत्रों के अन्तर्गत औद्योगीकरण हुआ है।

साहित्य अवलोकन

(1) Rajinder Singh, Prof. BK Agrwal (2021) "Growth of the Manufacturing Sector of Uttarakhand in Comparison with India" अध्ययन में पाया गया कि उत्तराखण्ड की औद्योगिक नीति राज्य के औद्योगिक विकास, औद्योगिक संवृद्धि और नई नौकरियों की रचना में हितकारी रही। उत्तराखण्ड की औद्योगिक नीतियों ने राज्य के औद्योगिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और राज्य कई उद्योगों के लिए विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की योजना की शुरूआत की है। इन पहलों ने औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखण्ड के विकास को गति दी है।

(2) MC Pande (2014) "Impact of State Industrial and Infrastructure Developoment Corporation of Uttarakhand Limited (SIIDCUL) on the economoy of uttarakhand" अध्ययन में पाया गया कि सिडकुल के अस्तित्व में आने के पश्चात् औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उत्तराखण्ड राज्य अपनी नीति में सफल है। परन्तु पूरे राज्य का जिलेवार विश्लेषण करने पर पाया गया कि, मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक निवेश हुआ है, और पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में रोजगार मे अधिक अवसर प्रदान किए गये हैं। उधमसिंहनगर, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल ने निवेश को आकर्षित किया है और उत्तराखण्ड के अन्य नौ जिलो को सिडकुल के माध्यम से कोई निवेश नहीं मिला है। अध्ययन में पाया गया कि पर्वतीय क्षेत्र में बड़े निवेश की कमी के कारण छोटे उद्योग ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।

(3) Rajender Singh, Prashant Kumar and Rahul Sharma, (2021)"Growth of the Manufacturing Sector of Uttarakhand in Comparison with India" अध्ययन में पाया गया कि उत्तराखण्ड के शुरूआती वर्षों में विनिर्माण की वृद्धि उच्च थी, लेकिन कुछ समय बाद विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर घट रही है। जो चिंता का कारण है, वर्तमान अध्ययन समस्त रूप से भारत के नाममात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना उत्तराखण्ड के नाममात्र और वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि का पता लगाने के लिए है। उत्तराखण्ड के नाममात्र और वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद और भारत के बंद घरेलू उत्पाद मे मौद्रिक संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। अध्ययन अवधि के दौरान उत्तराखण्ड के नाममात्र और वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रों की वृद्धि घट रही है, जो एक चिंता का विषय है।

अध्ययन का स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक है तथा प्राथमिक एवं द्वितियक समंकों पर आधारित है। समंकों का संकलन विभिन्न प्रकाशित सरकारी माध्यमों जैसे आर्थिक सर्वेक्षण रिर्पोट, सरकारी बेवसाईट पर उपलब्ध जानकारी, सिडकुल द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं, आर0 टी0 आई रिर्पोटों तथा विभिन्न लेखों, मासिक पत्रिका योजना और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित ऑकड़ों आदि से एकत्रित किया गया है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि

1. राज्य की अर्थव्यवस्था में ऊधमसिंह नगर में स्थापित औद्योगिकरण के योगदान का अध्ययन करना।
2. उत्तराखण्ड की आर्थिक नीतियों का सिडकुल में क्रियान्वयन का अध्ययन।
3. उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में सिडकुल के योगदान का अध्ययन।

परिकल्पनाः–

प्रस्तावित शोध कार्य "उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में सिडकुल का योगदान" का अध्ययन करने के लिए निम्न परिकल्पना की गई हैः

1. उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक विकास और ऊधमसिंह नगर के आर्थिक विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सीमाएँः–

1. उपर्युक्त शोध पत्र का क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के ऊधमसिंह जिलें में स्थापित सिडकुल तक सीमित रखा गया है।
2. उद्योगों के केवल आर्थिक पहलू पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

विश्लेषणात्मक अध्ययनः–

किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु औद्योगीकरण सर्वोत्तम उपाय है। क्योंकि औद्योगीकरण के माध्यम से ही उपलब्ध प्रकृतिक एवं माननीय संसाधनों का उचित दोहन किया जा सकता है। कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कमी, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, पूँजी निर्माण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के द्वारा देश का संतुलित विकास होता है। हमारा देश भी विकासशील राष्ट्र है इसलिए देश के आर्थिक एवं सर्वागीर्ण विकास एवं विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ने के लिए औद्योगीकरण अति आवश्यक है।

उत्तराखण्ड की औद्योगिक नीतियां

उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीतियों का सूत्रपात किया गया। उत्तराखण्ड की पहली औद्योगिक नीति राज्य गठन 9 नवंबर 2000 के ठीक बाद 2001 में पेश की गयी। राज्य के गठन से पूर्व राज्य उत्तरप्रदेश का एक भाग था, जिसमें के पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ाने हेतु कोई औद्योगिक नीति नहीं थी। पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं को भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी समस्याओं के लिए औद्योगिक नीति की आवश्यकता है। इन समस्याओं के निवारण हेतु उत्तराखण्ड सरकार ने सन् 2002 में उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की, जो उत्तराखण्ड के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है वर्ष 2003 में भारत सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य के लिए औद्योगिकरण की शुरूआत की थी, जिसमें उन औद्योगिक इकाइयों के लिए कई प्रोत्साहन शामिल किए गए थे, जो 10 वर्ष के लिए नामित औद्योगिक एस्टेट में उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार है इसको आगे बढ़ाते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने भी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। नई औद्योगिक नीति 2003 औद्योगिक विकास के लिए व्यवसाय को अकार्षित करने के लिए सफल रही परन्तु राज्य का सम्रग विकास सम्भव नहीं हो सका।

इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के पहलुओं पर अलग– अलग ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक औद्योगिक नीति की आवश्यकता थी, जिसे सरकार ने 2008 में विशेष एकीकृत औद्योगिक नीति के रूप में घोषित किया। उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों से संबंधित जिले के पिछड़ेपन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर श्रेणी अ और श्रेणी ब में विभाजित किया है।

श्रेणी अ में सुदूरवर्ती पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत और रूद्रप्रयाग जनपद का सम्पूर्ण भू– भाग शामिल किया है।

श्रेणी ब में पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा तथा बागेश्वर जनपद के सम्पूर्ण भू भाग के साथ देहरादून जनपद के विकासनगर, डोईवाला, सहरनपुर और रायपुर, इसी प्रकार नैनीताल जनपद के हल्द्वानी एवं रामनगर विकसखण्ड को छोड़कर अन्य भूभाग को शामिल किया गया है।

सरकार ने 2011 में नीति में संशोधन किया, जिसमें मामूली बदलाव के साथ नई घोषणा की गई कि पहाड़ी जिलों में 11 नए औद्योगिक एस्टेट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 2014 में सरकार ने विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया।

स्टार्टअप नीति 2023 उत्तराखण्ड राज्य की नीतियों में से एक महत्वाकांशी नीति है, जिसमें वर्तमान में 144 स्टार्टप्स तथा 13 इन्क्यूबेटर्स को राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गयी है। राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास, विश्व स्तरीय संस्थागत बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण और इन्यूबेशन परामर्शी नेटवर्क की स्थापना, पूंजी तथा बाजार तक पहुंच को बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2023 को प्रख्यात किया गया है। राज्य के गठन से पूर्व राज्य में 14,163 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयाँ पंजीकृत थी, जिसमें 700.29 करोड़ का पूंजी निवेश व 38,509 रोजगार उपलब्ध कराये गये थे। उत्तराखण्ड की औद्योगिक नीतियां सामाजिक –आर्थिक विकास में कारगर साबित हुई। जिसके परिणामस्वरूप उद्योगों की संख्या 2001–02 से बढ़कर 10 वर्षों में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो औद्योगिक नीतियों की बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई। इन नीतियों का औद्योगिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिस कारण प्रतिवर्ष उद्योंगो की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।

परिकल्पना का विश्लेषण

वर्ष	उत्तराखण्ड			ऊधमसिंह नगर	
	कुल उद्योगो की संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)	रोजगार की संख्या	कुल उद्योगो की संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)
2012 तक	25886	6511.970	139106	393	45857.48
2013	–	–	–	805	94828.07
2014	–	–	–	1235	116837.64
2015	33106	8648.484	195061	1693	144386.60
2016	–	–	–	2177	164932.26
2017	39324	10520.84	221907	2675	180307.26
2018	42253	11099.64	238678	3197	197544.59
2019	45660	11891.545	256866	3767	218628.59
2020	49809	12778.2	282597	4394	231752.59
2021	54725	13762.771	307932	5023	327220.59
2022	59798	14634.27	343922	5652	331192.59

स्रोतः– विभिन्न जनपदों के जिला उद्योग केन्द्रों से संकलित सूचना

उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश राज्य से अलग होने के पश्चात् राज्य में रोजगार की स्थिति बहुत संतोषजनक थी, रोजगार की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सिडकुल की स्थापना की। जिसमें राज्य की औद्योगिक नीतियों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिससे उत्तराखण्ड में उद्योगों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

उत्तराखण्ड में उद्योगों की वर्तमान स्थिति का विवरण

वर्ष 2022–23 तक

जनपद	उद्योगो की संख्या	रोजगार की संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)	उत्तराखण्ड में स्थापित कुल उद्योगो में से सिडकुल में स्थापित उद्योग
कुमाँऊ मण्डल				
उद्यसिंहनगर	9460	72378	4421.50	599
अल्मोड़ा	4200	11184	265.59	6
नैनीताल	4612	21398	1225.46	73
पिथौरागढ़	3412	8571	136.06	-
बागेश्वर	1981	4983	89.16	-
चम्पावत	2118	6261	107.09	-
कुल	**25783**	**124775**	**6244.86**	**678**
गढ़वाल मण्डल				
देहरादून	8235	66714	1850.23	311

हरिद्वार	10341	108475	5245.36	915
टिहरी	5951	18411	574.00	-
पौड़ी	5854	23493	781.36	400
चमोली	3083	7760	131.40	-
उत्तरकाशी	3055	7616	162.38	-
रूद्रपयाग	2523	7242	167.38	-
कुल	**39042**	**239711**	**8912.11**	**1626**
उत्तराखण्ड	**64825**	**364486**	**15156.97**	**2304**

स्रोत : विभिन्न जनपदों के जिला उद्योग केन्द्रों से संकलित सूचना

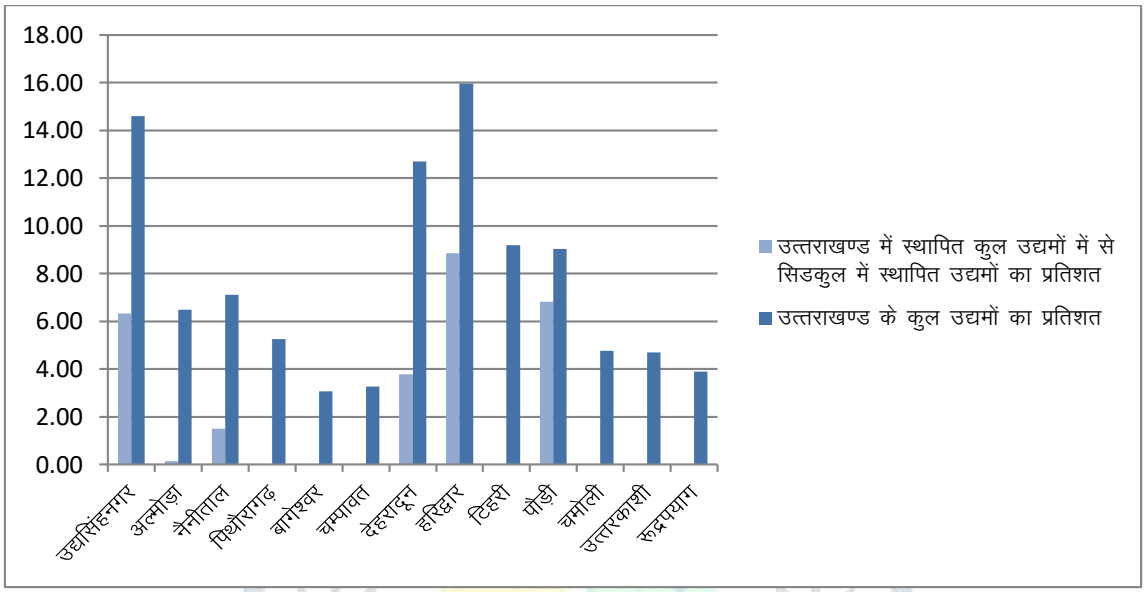

उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पूर्व राज्य में उद्योग विभाग/यूपीएस आई डी सी द्वारा औद्योगिक आस्थान विकसित किये गये थे। राज्य के गठन से पश्चात् यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रोकी भौतिक परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण सिडकुल को कर दिया गया है। सिडकुल द्वारा अब तक 2304 उद्योग 8471.77 एकड़ भूमि में स्थापित किये गये हैं। जिसका उत्तराखण्ड के कुल उद्योगों में योगदान 3.55 प्रतिशत का है। राज्य के कुल उद्योगों द्वारा 3,64,486 लोगो को रोजगार प्राप्त हुआ है।

उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक विकास और ऊधमसिंह नगर के आर्थिक विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

उपरोक्त तालिकाओं के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि औद्योगिक आस्थानों एवं सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानो में 2012 तक कुल उद्योगों की संख्या 25886 रही, जिसमें उपलब्ध रोजगार की संख्या 139106 रही, जो प्रतिवर्ष बढ़ती रही है। 2012 की तुलना में 2022 में उद्योगों की संख्या में 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो आर्थिक विकास में कारगर साबित हुई है। अन्य औद्योगिक आस्थानों की अपेक्षा सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में तीव्र गति से विकास हुआ है। उपरोक्त परिकल्पना उपलब्ध आंकड़ो के अनुरूप सही नहीं है, अतः इस परिकल्पना को निरस्त किया गया है।

निष्कर्षः–

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सिडकुल के अस्तित्व में आने के पश्चात् उत्तराखण्ड में प्रति वर्ष उद्योगो की संख्या में वृद्धि हुई है। जनपद ऊधमसिंह नगर कुमाँऊ मण्डल का तराई क्षेत्र है यहाँ का सम्पूर्ण भाग मैदानी है। यातायात

की सुविधाए पर्याप्त हैं, जिसके कारण यहाँ उद्योगों का विकास तीव्र गति से हुआ है। इसके विपरित पर्वतीय क्षेत्रो में उद्योगों का अपेक्षाकृत अभाव रहा। उत्तराखण्ड की औद्योगिक नीतियों ने राज्य के औद्योगिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, नीतियों की शुरूआत की गई वह उत्तराखण्ड के विकास में कारगर साबित हुई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

Singh, R., Agrawal, B. K. Prof**.,** (2021) A Review of the Uttarakhand's Industrial Policies and Their Performance. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD*, 5(5*)*, pp 1274-1280.

Pande M.C., Singh Chitranjan, (2014) Impact of State Industrial and Infrastructure Development Corporation of Uttarakhand Limited (SIIDCUL) on the economy of Uttarakhand, Asian Resonance, III(III), pp 301-304.

Singh, R., Kumar Prashant, Sharma Rahul., (2021) Growth of the Manufacturing Sector of Uttarakhand in Comparison with India, *Asian Journal of Economics, Finance and Management*, 5(1), pp 17-25.

दत्त, गौरव., महाजन अश्विनी, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 2018, पृ0 67

पुरी,वी0के0, मिश्र,एस0के0, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, 2014,पृ0 64

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

Statistical Diary 2021-22, Directorate of Economics and Statistics (2023), Dehradun '

औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड, वार्षिक प्रतिवेदन

http://www.siidcul.com/Home/AboutSIIDCUL.aspx

https://investuttarakhand.uk.gov.in/

https://doiuk.org/mysite/annual_report